मध्य प्रदेश में नक्सलवादी गतिविधियों से निपटने के लिए वित्तीय सहायता

3506. **श्री अजीत जोगी :**
श्री पृथ्वी माझी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने उस राज्य के कुछ जिलों में बढ़ती हुई नक्सलवादी गतिविधियों से निपटने के लिए केन्द्रीय सरकार से वित्तीय या अन्य सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने उस पर क्या दृष्टिकोण अपनाया है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार इस समस्या को हल करने के लिए कोई नई पहल करने का विचार रखती है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मुख्यत: यह राज्य सरकार ईसे संबंधित विषय है। तथापि, जब भी कोई आवश्यकता होगी, केन्द्र सरकार राज्य सरकार को सभी सम्भव सहायता देगी।

दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन

3507. **श्री अजीत जोगी**
श्री पृथ्वी माझी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्त आयोग और राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशों के आधार पर दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधनों को कब तक अंतिम रूप दे दिये जाने की संभावना है ; और

(ख) फौजदारी संबंधी मामलों के निपटान में होने वाले अनावश्यक विलम्ब को दूर करने के लिये और क्या नई पहल और कार्यवाही की जा रही है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) विधि आयोग और राष्ट्रीय पुलिस आयोग द्वारा की गई सिफारिशें, पर सरकार द्वारा अपनाये गये दृष्टिकोण के आधार पर दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1988 को सरकार ने 13-5-1988 को लोक सभा में प्रस्तुत किया था जो कि अभी तक उस सदन में लंबित है। अधिनियम की धारा 22, 28, 30, 31, 33 और 36 में प्रस्तावित संशोधन से फौजदारी मामलों का निपटान शीघ्रता से होगा।

Financial assistance to farmers under Insurance Scheme and Credit Guarantee Scheme

3508. SHRI PRAMOD MAHAJAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether any financial help is given to the farmers under the Deposit Insurance Scheme and Credit Guarantee Scheme; and

(b) if so, what are the details thereof for the last three years, Statewise?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) and (b) The present data reporting system does not generate the information in the manner asked for. However, deposits insured by the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) and the

extent of protection afforded to by it to depositors as at the end of 1985, 1986 and 1987 are furnished in the following table:

(Amount in crores of Rs.)

	1985	1986	1987
1. Assessable Deposits	76,517	86,214	103,044
2. Insured Deposits	56,211	62,878	75,511
3. Percentage of 2 to 1	73.05	72.9	73.3
4. Total number of accounts (in lakhs)	2,238	2,360	2,569
5. Fully protected accounts (in lakhs)	2,145	2,320	2,518
6. Percentage of 5 to 4	95.8	98.0	98.0

Further the year-wise amount of guaranteed advonces in respect of farmers and agriculturists for the last three years 1985, 1986 and 1987 (latest available), under the Small Loans Guarantee Scheme, 1971 of DICGC was Rs. 5057.75 crores, Rs. 6020.34 crores and Rs. 6428.29 crores respectively.

Cash credit to farmers

3509. SHRI PRAMOD MAHAJAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether a request was made to the Central Government to provide cash credit facility to farmers in Maharashtra; and

(b) if so, what are the details thereof and Central Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) and (b) The Reserve Bank of India (RBI) has reported that no such request was received by them. However, the public sector banks were advised by Government in April, 1988 to consider launching of credit card scheme on the lines of a scheme introduced by Dena Bank. The Scheme will facilitate the farmers with good track record to get the credit instantly and also dispense with execution of documents in each agricultural season. The Reserve Bank of India, in this regard, has reported that the Agricultural Credit Card Scheme has been introduced by Syndicate Bank, Canara Bank, Punjab National Bank, Andhra Bank, Bank of Maharashtra and Allahabad Bank, besides Dena Bank, on an experimental basis.

राष्ट्रीयकृत बैंकों में गैर सरकारी निदेशकों की नियुक्ति

3510. डा० अबरार अहमद खान: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम क्या है जिनमें गैर-सरकारी निदेशकों के पद आज की तारीख में रिक्त पड़े हैं ;

(ख) वर्तमान गैर-सरकारी निदेशकों को इन बैंकों में कब नियुक्त किया गया था और उनकी कार्यविधि कब समाप्त होनी थी ;

(ग) इस प्रकार के गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति के क्या मानदंड हैं; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार ऐसे पदों पर नियुक्त किये गये अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्तियों की संख्या क्या है ?